RAJYA SABHA

Friday, 28th February 1997/9th Phalguna 1918 (Saka)

The House met at eleven of the Clock

The Deputy Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*101. [The Question (Shri Ramdas Agarwal) was absent for answer vide col.. infra.]

Cost of Urea Production

*102. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:
SHRI JAGIR SINGH DARD:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the cost of production per unit of urea;

(b) the total taxes on urea;

(c) the average market price of urea;

(d) the element of profit;

(e) the proft being earned; and

(f) the steps taken to see that the prices of urea are kept low?

The Question was actually asked in the floor of the House by Dr. Shrikant Ramchandra Jichker.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (च) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) यूरिया की उत्पादन लागत अलग-अलग एककों के लिए भिन्न तथा हर माह भी भिन्न-भिन्न होती है जो अन्य बातों के साथ-साथ संयंत्र की स्थिति, पुरानेपन; प्रयोग किये गये फीडस्टाक, क्षमता उपयोग के स्तरों, विशिष्ट खपतों तथा इनपुटों की लागत पर निर्भर करती है। यूरिया एककों के लिए भारित औसत प्रतिधारण मूल्य इस समय 5434/- रु० है।

(ख) यूरिया पर स्थानीय करों और लेवियों का भार अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है तथा यह बिक्री मूल्य के शून्य से 7% से अधिक तक है।

(ग) 21.2.97 से पूरे देश में यूरिया का नियंत्रित निर्गम मूल्य 3660/- रु० प्रति मी० टन है।

(घ) यूरिया पर लागू प्रतिधारण मूल्य एवं राजसहायता योजना (आरपीएस) के अंतर्गत प्रतिधारण मूल्य में क्षमता उपयोग के नियामक स्तर पर शुद्ध मूल्य पर 12% कर पश्चात् लाभ शामिल होता है। लाभ की गणना विद्यमान निगमित कर की दर को शामिल करके की जाती है।

(ङ) कई क्रमिक मूल्य निर्धारण अवधियों से आरपीएस के अंतर्गत विभिन्न मानकों को सख्त बनाये गये हैं ताकि अधिक दक्षता स्तरों को प्राप्त करने के लिए एककों को प्रोत्साहित किया जा सके। प्रमुख परिवर्तन क्षमता उपयोग, संयंत्र के जीवनकाल, केटेलिस्ट के जीवनकाल आदि से सम्बद्ध है। जब तक ये मानदण्ड प्राप्त नहीं कर लिये जाते है तब तक अलग-अलग एकक शुद्ध मूल्य पर कर पश्चात 12% वांछित लाभ प्राप्त नहीं कर सकते है। प्रतिधारण मूल्य योजना (आरपीएस) में प्रोत्साहन और हतोत्साहन दोनों हैं, जिसके अंतर्गत यदि एकक का कार्य-निष्पादन प्रतिधारण मूल्य की गणना में अनुमानित विशिष्ट खपत और क्षमता उपयोग के मानदण्डों की तुलना में बेहतर है तो एकक की लाभप्रदत्ता में वृद्धि होती है। इसके विपरीत, यदि उत्पादन का स्तर कम है अथवा इनपुट खपत नियामक स्तरों से अधिक है तो या तो एकक की लाभप्रदत्ता में कमी आयेगी अथवा नुकसान होगा।

(च) स्वदेशी और आयातित यूरिया दोनों की लागतें 3660 रु० प्रति टन के नियंत्रित निगर्म मूल्य से काफी अधिक है। इस अन्तर को सरकार राजसहायता के रूप में वहन करती है।

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, Question no. 102 and 104 may be clubbed together.

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: No, No; there are two separate Ministers.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 102 and 104 are ...*(Interruptions)*...

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: No, Madam. Two separate Ministers are there.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes. One is Agriculture and there other is Chemicals.

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: If I am allowed four supplementaries, then I am agreeable for clubbing Question Nos. 102 and 104.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think both questions are yours.

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Madam, the hon. Minister has not replied to my question. My question is specific and very short: What is the cost of production of urea per unit? The hon. Minister has said, the cost of production of urea differs from unit to unit and even from month to month. It is true that the cost of production of more than 90% of the commodities in this country differs from unit to unit and from month to month. Everybody knows that the cost of production differs from month to month, from season to season and from unit to unit. But, we want to know the average cost of production in agriculture ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: From place to place.

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Yes, from place to place. In agriculture, every agricultural field differs. There are different climatic zones. Still, the Agricutlural Costs and Prices Commission declares the cost of production of almost all major agricultural commodities and publishes it. Now, why is the hon. Minister hiding the cost of production? If he replies to my question, then I will ask my first supplementary. First, he must reply to my question and give us the cost of production of five public sector units, five private sector units and five co-operative sector units. After clarification of this, I will ask my first supplementary.

SHRI AJIT P.K. JOGI: I think this is not a supplementary. This is only a clarification on the question.

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: No. This is not a supplementary.

श्री शीश राम ओला: माननीय उपसभापति जी, बहुत स्पष्ट यह 6 क्वैश्चन पूछे गए हैं-प्रति इकाई यूरिया की उत्पादन लागत कितनी है, यूरिया पर कुल कितना कर लगता है, यूरिया का औसत बाजार मूल्य कितना है, इसमें लाभ का अंश कितना है, इससे कितना लाभ अर्जित किया जा रहा है, और यूरिया के मूल्यों को कम रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? यह "क" से "च" तक जो क्वैश्चन माननीय सदस्यों ने पूछे हैं, उनका बहुत स्पष्ट उत्तर दे दिया गया है। प्रति इकाई यूरिया का औसत रिटेंशन प्राइस 5434/- रुपए है। टैक्स कितना लगता है, यह स्टेट पर निर्भर करता है, यह कोई सेन्ट्रल एक्साइज नहीं है, कुछ स्टेटस टैक्स लगाती हैं और कुछ स्टेटस नहीं लगाती हैं। यूरिया का औसत बाजार मूल्य 3660/- रुपए प्रति मी॰ टन है। इसमें लाभांश कितना है, अगर फैक्टरी ठीक चलती है, ठीक उत्पादन करती है तो 12 प्रतिशत शुद्ध लाभ माना गया है कि होना चाहिए। किसने कितना लाभ अर्जित किया, यह उसके खर्चे पर या कितने पैसे फैक्टरी पर लगाए, उसकी क्षमता और स्टैंडर्ड पर निर्भर करता है कि वह किस तरह से फैक्टरी को चलाता है। यूरिया की कीमत नीचे कैसे रखी जाए, इस पर स्पष्ट बता दिया गया है। सरकार यूरिया पर एक अच्छी सबसिडी देती है और इसलिए यूरिया की प्राइस पर कंट्रोल रखे हुए हैं।

डा॰ श्रीकांत रामचन्द्र जिचकर: नहीं, नहीं, मंत्री महोदय जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आप यह जो 5434 रुपए बोल रहे हैं, यह लागत मूल्य नहीं है, यह ऐवरेज रिटेंशन प्राइस है, यह कीमत है यूरिया की। मैंने लागत मूल्य पूछा है कि एक किलो यूरिया बनाने के लिए कितनी लागत लगती है, उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है? आपने अभी बताया कि 5434 रुपए। यह ऐवरेज रिटेंशन प्राइस आपने लिखा है, आपने कॉस्ट आफ प्रोडक्शन दिया नहीं। मेरा प्रश्न कॉस्ट आफ प्रोडक्शन का है, लागत मूल्य का है, आपने तो ऐवरेज रिटेंशन प्राइस को बोल दिया अभी कि यह कॉस्ट आफ प्रोडक्शन है। आप ही ने लिखा है कि यह ऐवरेज रिटेंशन प्राइस है। प्लीज गिव मी दि कास्ट आफ प्रोडक्शन।

श्री शीश राम ओला: माननीय सदस्य, आपने किलो के हिसाब से न तो पूछा है और न ही मेरे लिए बताना संभव है। किलो का हिसाब यूरिया पर नहीं बताया जा सकता।

डा० श्रीकांत रामचन्द्र जिचकर: किलो का नहीं तो 10 किलो का बताइए, 100 किलो का बताइए?

श्री शीश राम ओला: मुझे उत्तर देने दीजिए। ...(व्यवधान)...

उपसभापति: मंत्री जी को बोलने दीजिए। (व्यवधान)... वह बैठ गए हैं, आप बोलिए।

श्री शीश राम ओला: मेरा निवेदन यह है कि कोई भी कीमत स्थाई नहीं रहती है। हर तीन महीने में, हर दो महीने में, कभी-कभी महीने में कीमतें बदलती रहती है। यह बताना संभव नहीं है कि कोई कीमत स्थाई रहती है, इसलिए मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं कि प्रति किलोग्राम क्या कॉस्ट आती है। यदि माननीय सदस्य इसके लिए उत्सुक हैं तो मैं उन्हें यह जानकारी दे सकता हूं लेकिन इस पर बहुत समय लगेगा। सारी फैक्टरियों की, 21 फैक्टरियां हैं, सबकी ऐवरेज निकालना, मेरे ख्याल से यह कोई बहुत महत्व की बात नहीं है।

श्री हेच० हनुमनतप्पा: यह मंत्री जी के महत्व की बात नहीं हो सकती लेकिन सदस्यों के महत्व की बात है। यह महत्व की बात है इसीलिए तो एडमिट किया है। ...(व्यवधान)...

श्री शीश राम ओला: कृपया आप बताइए, एक किलो पर क्या महत्व दें, यूरिया मिलता है, यूरिया हम देते है।

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Madam, should I ask my first supplementary?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now you are asking a supplementary?

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: My first supplementary because the answer has not come. The Minister has said that he can't give the answer now and, if I am interested, he will supply the answer to me later. I am interested, Madam.

SHRI S.S. AHLUWALIA: It can't be for personal information. The House should know.

AN HON. MEMBER: The House should know.

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Let me clarify, Madam. The hon. Minister has said that this is not possible. The hon. Minister does not know, probably, that there is the Bureau of Industrial Costs and Prices (BICP). The BICP is sitting there doing this job, and this is not a difficult job. They are doing it, they are publishing it. There is a Fertiliser Mantri and Fertiliser News Bulletin; these things are regularly published I am very sorry that the Minister's officers do not seem to have briefed him properly. This is regularly done. And the hon. Minsiter has gone on record saying that this cannot be done and it is very difficult, and he has gone to the extent of saying that this is not important. For us this is very important. Anyway, I do not want to dilate on this matter; I want to ask my first supplementary now.

Madam, there is the average price retention mechanism, something like pooled prices. Now, these pooled prices or average retention prices are fixed on the basis of the cost of production of the private sector, public sector and cooperative sector units. What is happening now is that the public sector units are not functioning efficiently. Therefore, there cost of production is more. The private sector units are functioning efficiently, and so, their cost of production is less. But whenever the retention price is fixed, it is fixed on the basis of the cost of production of the public sector. So, huge amounts of profits are going to the private sector.

एक माननीय सदस्य: प्रश्न पूछ लीजिए।

डा० श्रीकान्त रामचन्द्र जिचकर: पूछ रहा हूं न भाई। आपके मंत्री महोदय ने ओरिजनल रिप्लाई भी नहीं दिया। इसलिए अब तो मेरे ऊपर और ज्यादा रिस्पांसिब्लिटी है कि उनको यह सब समझाऊं कि क्या चीज़ है क्योंकि उनके अफसरों ने तो शायद उनको समझाया नहीं। तो, सर, प्राइवेट सैक्टर में हॉयर रेट आफ प्रॉफिट मिल रहा है। Madam, I want to know whether the Minister will now publish all these reports of the cost of production of the private, public and cooperative sector

units so that we will know which private sector units are deriving huge benefits at the cost of this mechanism.

श्री शीश राम ओला: उपसभापति महोदया, ठीक है, मुझे सिखाएंगे माननीय सदस्य, मैं सीखने की चेष्टा करूंगा। उसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है।

डा० श्रीकांत रामचन्द्र जिचकर: मैंने "सिखाना" इस शब्द का प्रयोग हीं किया है। मैंने कहा कि यह मेरा जिम्मेदारी है कि मैं मंत्री जी को बताऊं ...**(व्यवधान)** मैं इनसे बहुत छोटा हूं, मैं सिखा नहीं सकता इन्हें।

उपसभापति: समय जा रहा है। आपको सवाल का जवाब चाहिए, वह ले लीजिए।

श्री शीश राम ओला: उपसभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने मुझ से पूछा है प्रति इकाई न कि प्रति किलोग्राम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रति इकाई के हिसाब से मैंने उत्तर दिया है। यदि प्रति किलोग्राम पूछेंगे तो उसकी भी ऐक्सरसाईज़ करवाकर इन्हें उत्तर दिया जाएगा। इन्होंने प्रति इकाई पूछा है, प्रति किलोग्राम नहीं पूछा।

दूसरी बात यह है कि बी०आई०सी०पी० यूरिया की लागत तय नहीं करती, एफ०आई०सी०सी० तय करती है। हमसे संबंधित बात जो थी, वह मैंने आपको बताने की चेष्टा की है। यदि कोई बात अस्पष्ट है तो कृपया मुझे पूछें।

THE DEPUTY CHAIRMAN: This is his last supplementary.

डा० श्रीकांत रामचन्द्र जिचकर: मैं लास्ट सप्लीमेंटरी पूछता हूं लेकिन मंत्री जी को और क्लेरिफाई कर देता हूं।

I asked the question in English. It says: "the cost of production per unit of urea;" Per unit may be one kilo, ten kilos, 100 kilos or one tonne. Some units is there. I have asked my question specifically. I asked for the cost of production per unit of urea. Whether their unit is kilo or tonne or metric tonne or gramme, whatever it is, he should have given it. He has not given it.

Anyway, my second supplementary is this. It is compulsory for private companies under the Companies law to submit the cost audit report to the Government. So, private companies have to submit their cost audit report to the Government. He has just now said that the BICP monitors it. The BICP collects the cost of production from these reports. So, these cost audit reports are compulsorily required to be given by these companies. I want to know whether the Minister will lay all these mandatory cost audit reports of these 21 companies on the Table of Parliament so that we will come to know that the cost of production is and where.

SHRI V. NARAYANASAMY: Even if the Minsiter is not able to give it now.

श्री शीश राम ओला: महोदया, मेरा निवेदन यह है कि यूरिया का औसत रिटेशन प्राईस 5434 रुपए प्रति मीट्रिक टन है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: One minute, please.

डा० श्रीकांत रामचन्द्र जिचकर: प्राईस पर मैं हूं ही नहीं। मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछ रहा हूं

उपसभापति: मंत्री जी, वह प्राईस नहीं पूछ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल में उनका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेल में कितना प्रॉफिट है। वे उसके बारे में पूछ रहे हैं।

श्री शीश राम ओला: नोमेटिव नेट प्रॉफिट 12 प्रतिशत है। अगर अच्छी कंपनी है, पूरा प्रोडक्शन कर रही है तो हम मानते हैं कि 12 परसेंट उसको लाभ होना चाहिए। लेकिन अमूमन ऐसी कंपनियां भी है या तो जिन में रिप्युअल रिप्लेसमेंट पर खर्चा पूरा नहीं किया गया है या उनकी कार्यक्षमता में कहीं कमी है। ऐसी कंपनियों में पूरा प्रोडक्शन नहीं हो पाता। इसलिए उन्हें पूरा लाभ नहीं हो पाता है। वैसे 12 प्रतिशत से अधिक लाभ अधिक क्षमता उपयोग के बिना संभव नहीं है।

डा० श्रीकांत रामचन्द्र जिचकर: आपने आश्वासन नहीं दिया।

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Madam, if the details are not available with him, now kindly ask him to send them later. He has assured this.

डा० श्रीकांत रामचन्द्र जिचकर: कृपया आप मुझे ये सब डिटेल्स भेजें।

श्री जागीर सिंह "दर्द": मैडम, मैं आपकी मारफत यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब में सबसे ज्यादा

खपत होती है यूरिया की। इस समय यूरिया की कीमत 3,660 रुपए प्रति मीट्रिक टन है। मैं पूछना चाहता हूं कि बाजार में जो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे?

श्री शीश राम ओला: मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यूरिया एक कंट्रोल्ड आईटम है। इसे हम बाहर विदेशों से भी मांगते है और वह हमें 8,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन से ज्यादा ही पड़ता है। सरकार सब्सिडी देकर इसको किसानों को सस्ते भाव कर देती है। इस तरह इस पर हमारा पूरा कंट्रोल है।

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Madam, as my friend, Dr. Jichkar said, private companies are amassing huge amount of profits in the present mechanism. In fact, the Government is also going in for joint venture and private venture projects. Will the Government allow these units to sell their own urea and pass on the subsidy portion to the farmers? The farmers are not aware of the subsidy that they are giving. When the farmer is passed on the urea, he should be able to know what amount of subsidy the Government is bearing per quintal of urea or the fertiliser that he is purchasing. Instead of putting the subsidy in the production cost, will the Government offer to pay the subsidy to the farmers at the retail level so that whichever company, which is not working profitably also improves its productive capacity and the efficiency of the farmer also in turn will know the subsidy portion that the Government is paying to them.

श्री एस०एस० अहलुवालिया: आप तो हिन्दी जानते हैं, हिन्दी में बोलिए।

श्री हेच० हनुमनतप्पा: हिन्दी आपकी मातृभाषा है, हमारी नहीं।

श्री एस०एस० अहलुवालिया: क्या कह रहे हैं, यह भाषा है यह।

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is his problem.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I am not insulting the national language, but you cannot force me to talk in a particular language.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Are you going to accept it that English is your mother tongue?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: No.

SHRI S.S. AHLUWALIA: If you say Kannada is your mother-tongue, I will appreciate it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is allowed to speak in English and in Hindi.

श्री एस०एस० अहलुवालिया: महोदया, ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए।

उपसभापति: नहीं उनकी मरजी है वह बोले अंग्रेजी में। आपको क्या ऐतराज है।

श्री एस०एस० अहलुवालिया: हम पूरी भारत माता के बच्चे हैं।

उपसभापति: ठीक है, भारत माता के सब बच्चे हैं और वह अंग्रेजी में बोल रहे है। बैठिए।

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I do not want to take a lesson from him. I am sorry, he should know his limits. It is going into the records.

SHRI S.S. AHLUWALIA: I know, but you should also restrain yourself.

श्री शीश राम ओला: महोदया, किसान को यूरिया का मूल्य कम होने से स्वतः ही सब्सिडी मिल जाती है। पर, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि 1904 रुपए प्रति टन सब्सिडी स्वदेशी यूरिया पर दी जाती है।

श्री हेच० हनुमनतप्पा: मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है।

उपसभापति: मंत्री जी, उन्होंने सवाल यह किया है कि आप सब्सिडी देते है प्रोडक्शन यूनिट को, जो कोई यूनिट जो है प्रोफिटेबिल नहीं है। इनका सवाल है कि अगर फार्मर्स को मालूम हो जाए कि उन्हें कितनी सब्सिडी मिल रही है तो फार्मर्स को उसका बेनिफिट मिलेगा, प्रोडक्शन यूनिट को बेनिफिट मिलेगा। मुझे लगता है कि उनका यह सवाल

श्री शीश राम ओला: उपसभापति महोदया, निवेदन किया है कि 1904 रुपए देते हैं, सब किसान को मालूम है। मैं भी इनसे बड़ा किसान हो सकता छोटा नहीं हूं।

DR. MOHAN BABU: Urea accounts for 85 per cent of the total fertiliser production. In 1995-96, urea production was 158 lakh tonnes. For 1996-97, 162.73 million tonnes is the target. If enough gas does not reach the Vijipur unit, the expected increase in the total production of urea will not take place. So what are the steps taken by the Government to achieve the target?

श्री शीश राम ओला: उपसभापति महोदया, इसके कई कारण हैं। प्रोडक्शन कभी खपत कम होने से कम हो जाता है, कभी बिजली की कमी है, कभी गैस की कमी है। कई कारण है उत्पादन कम होने के। पर, सरकार चेष्टा कर रही है कि हमारे राष्ट्र में इतना उत्पादन हो कि हम यूरिया में आत्मनिर्भर बन जाएं।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: महोदया, मैं जानना चाहता हूं मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अब उन्होंने 3660 रुपया प्रति मैट्रिक टन यह इश्यू प्राईस तय की है और यह इश्यू इंपोर्टेड यूरिया को मिलाकर के है और आप यह कहते हैं कि अगर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इस कीमत को कम कर सकते हैं। हालत तो यह है कि जितना आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उससे ज्यादा इंपोर्ट हो जाता है। बच जाता है इंपोर्टेड यूरिया। पच्चीस लाख टन उर्वरक का भंडार आपके पास रह गया है। उसकी कीमत, उसके ब्याज का खर्चा जुड़ कर आपका ईश्यू प्राइस बनता है। इन दोनों में मेल कैसे बैठेगा? घटाने का इरादा या घटाने का प्रोग्राम आपका किस प्रकार का है ताकि यूरिया के ईश्यू प्राइस को कम किया जा सके?

श्री शीश राम ओला: ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि यूरिया के भंडार देश में कहीं पर्याप्त मात्रा में या जरूरत से ज्यादा पड़े हैं। स्थिति यह है ...**(व्यवधान)**...

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: जरूरत से ज्यादा का मतलब क्या है? आपको जितना स्टॉक चाहिए क्या उससे ज्यादा स्टॉक नहीं है?

श्री शीश राम ओला: नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें स्टेटवाइज़ ऐलोकेशन करना पड़ता है, ऐलॉटमेंट करना पड़ता है। स्टेट जो हमसे चाहती है वह हम कृषि मंत्री को देते हैं, वे हर स्टेट को भेजते हैं जो स्टेट मांगती है। स्टेट के पास कोई भंडार है तो यह स्टेट की ज्यादा जिम्मेदारी है। स्टेट हमसे कहती है कि इतना आपको देना है हमें और हम चेष्टा करते हैं कि उतना स्टेट को मिले एक बात। दूसरी बात, यूरिया एक निश्चित समय पर काम आता है और वह समय बुआई और सिंचाई के वक्त काम आने का है। तब यदि यूरिया नहीं है तो सारे राष्ट्र में उसकी बहुत मांग बढ़ती है, इसलिए उस वक्त यूरिया देना अत्यंत आवश्यक है और एक दिन में यूरिया प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह एक छोटा सा समय होता है बुआई और सिंचाई का, तब पर्याप्त मात्रा में यूरिया का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा या सही नहीं होगा कि हमारे पास अथाह भंडार यूरिया का पड़ा है फिर भी हम विदेश से मंगा रहे हैं। हमें आवश्यकता है तभी तो हम मांगते हैं।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: लेकिन समय पर जहाज़ नहीं जाते, मांग समाप्त होने के बाद जहाज़ आते हैं इसलिए स्टॉक पड़ा रहता है। इसका कुछ इंतज़ाम करने का इरादा है?

श्री शीश राम ओला: अपनी बात का तो स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं माननीय सदस्य। मैं क्या करूं यदि जहाज़ से नहीं आए और कोई स्टेट हमसे यूरिया मांगे तो हम कहां से देंगे? इसलिए हमें स्टॉक रखना अत्यंत आवश्यक है और स्टॉक होगा तभी तो दे पाएंगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let the Minister reply. I can't ask every Member to raise a supplementary question. There is another question on the same subject. I think Q.No. 104. We cannot spend so much time on this question alone.

श्री एस० एस० सुरजेवाला: उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यहां कृषि मंत्री ने इसी हफ्ते फर्टिलाइज़र्स की प्राइस के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट में उन्होंने यह बात कही थी कि यूरिया की कीमत जो 10 परसेंट इनक्रीज़ की है 21 फरवरी से, एक हफ्ता पहले, उसके कारण ये हैं कि फॉस्फेटिक और पोटासिक जो फर्टिलाइजर्स हैं, जिनको एन०पी०के० कहते हैं, चूंकि उनकी कीमतों को कम कराने के लिए गवर्नमेंट ज्यादा सबसिडी दे रही है, इसलिए वह जो नुकसान है, उसको पूरा करने के लिए 10 परसेंट यूरिया की कीमतें बढ़ाई गई हैं, यह मंत्री जी ने इस हाउस में बयान दिया था। मैं उर्वरक मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस सारी एक्सरसाइज़ का क्या फायदा है कि एक तरफ आप किसान को जो जरूरी फर्टिलाइज़र्स हैं, उन पर कंसेशन देना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो किसान सबसे ज्यादा यूरिया इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप 10 परसेंट इनक्रीज़ करके उन्हीं किसानों की जेब से ज्यादा पैसा बाहर निकालना चाहते हैं? क्योंकि जो रोशियों दोनों में है उसमें

ज़मीन-आसमान का फर्क है इसलिए सरकार की यह नीति उचित नहीं है। तो क्या आप यह जो 10 परसेंट यूरिया की कीमतों में वृद्धि की है, इसे वापस लेंगे?

दूसरी बात, एक ओर बड़ी एनॉमली यह है कि इन्होंने 21 फरवरी से यूरिया की कीमतें बढ़ाने का एलान किया है और पहली अप्रैल से ये कीमतें लागू होंगी।

अभी तक जो भी स्टॉक स्टाकिस्ट के पास था, उन्होंने सारे का सारा रोक लिया है और किसान को कोई भी यूरिया 21 तारीख की अनाउंसमेंट के बाद पुराने प्राइस पर नहीं मिलेगा। तुरन्त उन्हें इन्क्रीज़ लागू कर देना चाहिए था। तो इस बीच में जो लाखों-करोड़ों रुपये उस स्टॉक से कम्पनियां कमाएंगी, मंत्री जी उसे वापिस लेकर क्या किसानों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे?

श्री शीश राम ओला: माननीय उपसभापति महोदया, माननीय सदस्य ने बड़ा अहम क्वेश्चयन पूछा है। वह काफी सीनियर है और मंत्री भी रहे हैं, वह किसान भी हैं। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यूरिया के भाव इतने सस्ते थे और जमीन का उर्वरक संतुलन इतना बिगड़ गया था कि सस्ता होने के नाते किसान यूरिया अधिक उपयोग करते थे जो उचित नहीं था। जमीन के संतुलन के बिगड़ने से उसकी उपजाऊ शक्ति नहीं रही जो खाद डालने पर हो सकती थी इसलिए यूरिया के 10 प्रतिशत दाम बढ़ाने से हमको 710 करोड़ के लगभग बचत होगी, 10 प्रतिशत से। उसमें हमने एक अप्रैल से, सब्सिडी डी०ए०पी० पर जो 3000 रुपये प्रतिटन थी, उसके स्थान पर 3725, आयातित डी०ए०पी० पर 1500 थी, उसके स्थान पर 2250, पोटाश पर 1500 की जगह दो हजार और एस०एस०पी० पर 500 की जगह 600 एक अप्रैल से कर दिया है ताकि उसका पूर्ण लाभ हमारे किसानों को मिले।

श्री एस० एस० सुरजेवाला: मैडम मेरे दूसरे पार्ट का जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया था कि जो स्टॉक था, उस स्टॉक का क्या बनेगा?

श्री शीश राम ओला: स्टॉक के लिए....

उपसभापति: मंत्री जी हो गया। क्वेश्चयन नं० 103।

Rise in the Prices of Major Agricultural Inputs

*103. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the percentage of rise in the prices of major agricultural inputs during the years 1995-96 and 1996-97;

(b) the percentage of rise in the support price of major foodgrains during this period; and

(c) the percentage of rise in the production of these foodgrains during this period?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) to (c) A statement is laid on the table of the house.

Statement

(a) to (c) Statement showing the annual percentage variations in the prices of major agricultural inputs as measured by the wholesale price index numbers, the minimum support prices of foodgrains and the production of foodgrains during the years 1995-96 and 1996-97 are given at statement I, II and III respectively.

Statement-I

Percentage annual variation in the prices of major agricultural inputs during 1995-96 and 1996-97 as measured by the wholesale Price Index Numbers (Base 1981-82=100)

Commodities	Weight (%)	1995-96	1996-97 (as on 8.2.1997)
Fertilizers	1.748	5.1	−0.8
Pesticides	0.202	−15.4	0.5
High Speed Diesel	2.164	0.0	14.8
Lubricants	0.453	9.6	3.6
Light Diesel Oil	0.203	−0.1	29.6
Electricity for Irrigation	0.317	0.0	13.8
Tractors	0.348	5.9	8.5
Power Driven Pumps	0.208	7.2	16.3
Average	5.638	2.4	8.7